केंद्रीय बजट 2023-24

//

Drishti IAS

केंद्रीय बजट 2023-24

अमृत काल का पहला बजट

भाग - A

बजट और अमृत काल

- विज़न- सशक्त, समावेशी अर्थव्यवस्था (प्रौद्योगिकी-चालित, ज्ञान-आधारित एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ)

बजट के सप्तर्षि

- समावेशी विकास:
  - कृषि:
    - कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
    - कृषि-स्टार्टअप्स के लिये कोष की स्थापना
    - बागवानी फसलों के लिये आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम
    - भारत को कदन्न अर्थात् 'श्री अन्न' (पोषक अनाज/कदन्न) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाना
  - शिक्षा एवं कौशल:
    - शिक्षण प्रशिक्षण का सुधार
    - राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना
    - पंचायत/वार्ड स्तर पर पुस्तकालयों की भौतिक उपस्थिति
  - स्वास्थ्य:
    - 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय
    - सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु मिशन
- अंतिम छोर तक पहुँचना:
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया
  - PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा (निधि-15,000 करोड़ रुपए) प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिये भारत श्री की स्थापना की जाएगी
  - प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिये भारत श्री की स्थापना की जाएगी
- अवसंरचना और निवेश:
  - पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए (अब GDP का 3.3%)
  - राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का फैसला
  - टियर 2/3 शहरों के लिये शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना की जाएगी
- क्षमता उभारना:
  - कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन (3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया)
  - विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिये जन विश्वास विधेयक पेश किया गया
  - ई-न्यायालय चरण III
- हरित विकास:
  - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
  - गोबरधन (GOBARdhan) योजना- 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्र
  - पीएम प्रणाम- वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना
  - मिष्टी (MISHTI) initiative for mangrove plantation
- युवा शक्ति:
  - पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी
  - राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- वित्तीय क्षेत्र:
  - MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया
    - अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण
    - क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी
  - महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र- एकमुश्त नई लघु बचत योजना - 2 वर्ष के लिये (मार्च 2025)

राजस्व प्रबंधन

- राजस्व घाटा:
  - 6.4% (वित्तीय वर्ष 22-23)
  - जीडीपी का- 5.9% अनुमानित (वित्तीय वर्ष 23-24)
  - लक्ष्य - <4.5% (वित्तीय वर्ष 25-26 तक)
- राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमति

[और पढ़ें....]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/union-budget-2023-24-1